



# जिले की 2 लाख 1 हजार 211 लाड़ली बहनों के खाते में आई लाड़ली बहना की राशि

**सिंगरौली।** प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दमोह जिले के सिंगरामपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सिंगल किलक से लाड़ली बहनों के खाते में सिंगल किलक से 1.29 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 55 लाख हितग्राहियों को 332.71 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। साथ ही सिंगल किलक से लाड़ली बहना योजना की 24 लाख बहनों के बैंक खाते में एलपीजी गैस सिलेंडर अनुदान की 28 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई। प्रत्येक सिलेण्डर 450 में दिया जा रहा है।

सिंगरौली जिले की लाड़ली बहना योजना की 2 लाख 1 हजार 211 बहनों के खाते में मुख्यमंत्री ने सिंगल किलक के माध्यम से राशि अंतरित की। प्रत्येक हितग्राही के



05.10.2024 14:52

बैंक खाते में 1250 रुपए की राशि अंतरित हुई। यह छोटी सी राशि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहाया साबित हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि आज हमारे प्रदेश की गौरव रानी दुर्गावती का 500वां जन्मदिवस है। साथ ही नवाचात्रि का पावन पर्व है। इस अवसर पर बहनों के बैंक खाते में लाड़ली बहना योजना की राशि जारी की गई है। इस राशि में लिए सदैव प्रयास करती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती के सम्मान में उनकी प्रथम राजधानी दमोह जिले के सिंगरामपुर में आज मध्यप्रदेश सरकार के मैट्रिमेंटल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान परिवारों को शून्य प्रतिशत व्याज पर ऋण देने का नियंत्रण परित किया गया है। सरकार किसानों के कल्याण के बैंक खाते में लिए वृद्धि की जाएगी।

## धन एवं मोटे अनाजों के उपार्जन के लिए पंजीयन

### 14 अक्टूबर तक

**सिंगरौली।** किसानों के उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए शासन द्वारा किसानों से नियरित समर्थन मूल्य पर धन, ज्वार तथा बाजारा का उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन के लिए किसानों का अनन्तालाइन पंजीयन होना आवश्यक है। अनन्तालाइन पंजीयन 14 अक्टूबर तक किया जायेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी पी.सी. चन्द्रवर्णी ने बताया कि किसान ग्राम पंचायत कार्यालय के सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों एवं खरीदारी केन्द्रों में निःशुल्क पंजीयन करके राज्य का छिड़काव कराया गया है। इसके साथ ही रहवासियों को देमो के माध्यम से समझाया गया कि गोली और सूखे कचरे को एक साथ देने से प्लाट में काम कर रहे सफाई मिस्रों को असुविधा होती है। इन उनको स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं के साथ कचरे को अलग करने में सहायता देता है। इसके अलावा किसान एपी कार्यक्रम सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे में 50 रुपए का शुल्क तथा आवश्यक दस्तबोज देकर 14 अक्टूबर तक उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं।

## नगर निगम के वार्ड 42 में चला विशेष साफ सफाई अभियान

नगर निगम आयुक्त ने किया स्कॉलर टेक्नो मॉडल स्कूल का औचक निरीक्षण



अलग-अलग करके रहवासी नहीं देते हैं तो उनका कचरा नहीं लिया जाएगा। और उपर जुमाने की कार्रवाई की जाएगी द्य सफाई के दौरान राजेश किराना स्टोर सहित अन्य दुकानों पर कचरा का सही प्रबंधन और सफाई कर जावेगा। इसके बाद निगम आपूर्ति अधिकारी पी.सी. चन्द्रवर्णी ने बताया कि किसान ग्राम पंचायत कार्यालय के सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों एवं खरीदारी केन्द्रों में निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। एपी किसान एपी अपने एन्ड्रायड मोबाइल पर डाउनलोड करके किसान स्वयं पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान एपी अनन्तालाइन कियोक सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे में 50 रुपए का शुल्क तथा आवश्यक दस्तबोज देकर 14 अक्टूबर तक उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं।

## पीएम किसान सम्मान निधि से जिले के कृषक हुए लाभान्वित

जिले के लगभग पच्चीस हजार किसानों ने प्रधानमंत्री के उद्घोषन को सुना एवं खुशी जाहिर की



सिंगरौली। देश के प्रधान राजेन्द्र मेश्राम, मराहाई श्रीमती रानी अग्रवाल, विकास किसान सम्मान निधि की 18 वीं किश्त का वाशिंग महाराष्ट्र से सिंगल किलक के माध्यम से हस्तान्तरण किया गया। सिंगरौली जिले के कुल 133401 हितग्राही हुए लाभान्वित। कलेक्टरेट सभागार में सिंगरौली विधान सभा के विधायक राम प्रदेश के विधायक राम निवास शाह, देवसर विधायक के विधायक



## संपादकीय

## महायुद्ध का खतरा

ईरान द्वारा इजरायल को सीधे निशाना बनाने से महायुद्ध जैसे हालात बना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक और दुखद है। तनाव चरम पह है, क्योंकि इजरायल की भी बढ़ते इरान पर जवाबी बार कर सकता है। दरअसल, लगातार एक साल से ईरान प्रवासी रूप से संघर्ष दिखा रहा था। इन्जुल्हाह जैसे आतंकी संगठनों को हर तरह की मुश्किल देकर खुद को सीधे युद्ध में उत्तरने से बचा रहा था, पर मंगलवार को एक साथ 180 मिसाइलें दागकर इजरायल को उसने साफ करने दे दिया है कि वह अब ऊपर नहीं बैठेगा। खालिकर, नसरलाह की मौत के साथ यह जांग में कूदने का भारी बदलाव था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहु ने भी साफ कह दिया है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल के साथ समर्थन वाले हैं कि वह बदले की मानसिकता में फासा हुआ है और किसी भी नसरलाह पर कान नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भी वह रसी भर भाव देने को तैयार नहीं है। अमेरिका से मिल रहा समर्थन उसके लिए पर्याप्त है। ऐसे में, एक महायुद्ध दर्दी पर दस्क देने लगा है। आज एक बड़ा सवाल है कि वह इजरायल, ईरान जैसे दोनों द्वारा इजरायल पर हाल बोला भी उसे नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इजरायल ने उनको मार गिराया था। ईरान का कहना था, यह हमला उसने सतीया में ईरानी दूसरास पर हमले के बदले में किया था, जिसमें 15 से अधिक ईरानी कर्मचारियों की मौत हुई। दूसरी घटना, जनवरी 2020 की है, जब अमेरिका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनीरी गाई के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने मिसाइलों के जरिये इरान में मीजूद अमेरिकी सेयर अंडोर पर हमला बोला था। जिसके बाद मामला शांत हो गया था। तब बेशक तनाव के बादल छंट गए थे, किन इस बक श्वेतीय और अंतर्राष्ट्रीय तरवीर बदली हुई है।

एक बड़ा बदलाव तो यही है कि इजरायली प्रधानमंत्री अब आक्रामक नीति अपना रहे हैं। इसकी वजह यही है कि उन्होंने घोषणा की है कि ईरान के दोनों छत्ते गृह-हमास और हिजबुल्लाह का सफाया होकर ही रहेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ तो कई हफ्तों से इजरायल का आक्रमण जारी है। पहले पेजर-वॉकीटोंकी विस्फोट से इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को ध्वस्त किया और फिर नसरलाह के साथ-साथ कई हिजबुल्लाह नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। लगता यही है कि नेतन्याहु की महत्वाकांक्षा अब हमास या हिजबुल्लाह के साथ कीमत नहीं रख रही है।

## पश्चिम एशिया में बदले की बेरहम बयार

(विवेक काटज़, पूर्व राजनीतिक) मंगलवार की देर शाम ईरान का इजरायल पर मिसाइल हमला करना कई आतंकों को आधार दे रहा है। इजरायल ने बेशक ईरान की ज्यादातर दोनों छत्ते गृह-हमास और हिजबुल्लाह का सफाया होकर ही रहाया। हिजबुल्लाह के खिलाफ तो कई हफ्तों से इजरायल का आक्रमण जारी है। पहले पेजर-वॉकीटोंकी विस्फोट से इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को ध्वस्त किया और

हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काफी अधिक बढ़ गया है। उन्होंने घोषणा की है कि ईरान के दोनों छत्ते गृह-हमास और हिजबुल्लाह का सफाया होकर ही रहेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ तो कई हफ्तों से इजरायल का आक्रमण जारी है। पहले पेजर-वॉकीटोंकी विस्फोट से इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को ध्वस्त किया और

बहरहाल, मवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सुक्ष्मा परिषद इस पर चिंतन कर रही है और यह अन्यान्य स्थानांतरिक है कि वह इजरायल और ईरान, दोनों से शांति की अपील करेगी। सच यह भी है कि दुनिया की महाशक्तियां महायुद्ध नहीं चाहतीं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में उत्तरा हुआ है और रूस फिलहाल यूक्रेन मोर्चा पर ही सिमटे रहना चाहता है। रही बात

यहाँ दो घटनाओं का जिक्र आवश्यक है। पहली, अप्रैल, 2024 में ईरान ने डोन व मिसाइलों द्वारा इजरायल पर हाल बोला था और उस बदले की नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इजरायल ने उनको मार गिराया था। ईरान का कहना था, यह हमला उसने सतीया में ईरानी दूसरास पर हमले के बदले में किया था, जिसमें 15 से अधिक ईरानी कर्मचारियों की मौत हुई। दूसरी घटना, जनवरी 2020 की है, जब अमेरिका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनीरी गाई के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने मिसाइलों के जरिये इरान में मीजूद अमेरिकी सेयर अंडोर पर हमले के बदले में किया था, जिसमें 180 मिसाइलें दागकर हिमायब बराबर हिमायब नसरलाह की मौत का बदला लेने के लिए उत्तरा है और अब अगर इजरायल की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई होती है, तो यह समर्थन उसके लिए पर्याप्त है। ऐसे में, एक महायुद्ध दर्दी पर दस्क देने लगा है। आज एक बड़ा सवाल है कि वह इजरायल, ईरान जैसे दोनों द्वारा इजरायल पर हाल बोले नहीं चाहते हैं? दरअसल, हर देश द्वितीय में आम जनमानस को लेकर सजगा है। संसार के ज्यादातर लोग महायुद्ध नहीं चाहते, इसलिए बड़ी आक्रामकता दिखाने के बावजूद देश अपना बचाव भी कर सकता है। ईरान यह मानता है कि उसने 180 मिसाइलें दागकर हिमायब बराबर हिमायब नसरलाह की तरफ से किया था और किसी भी नसरलाह पर कान नहीं दे रहा है। ईरान यह मानता है कि उसने 15 से अधिक ईरानी कर्मचारियों की मौत हुई। दूसरी घटना, जनवरी 2020 की है, जब अमेरिका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनीरी गाई के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने मिसाइलों के जरिये इरान में मीजूद अमेरिकी सेयर अंडोर पर हमले के बदले में किया था, जिसमें 180 मिसाइलें दागकर हिमायब बराबर हिमायब नसरलाह की मौत का बदला लेने के लिए उत्तरा है और अब अगर इजरायल की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई होती है, तो यह समर्थन उसके लिए पर्याप्त है।



फिर नसरलाह के साथ-साथ कई हिजबुल्लाह नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। लगता यही है कि नेतन्याहु की महत्वाकांक्षा अब हमास या हिजबुल्लाह तक ही सीमित नहीं रह गई है। 1 अक्टूबर के अपने टीवी संस्करण में उन्होंने ईरान की जनता को उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सरकार के खिलाफ उत्तराधीन और अपील की कि वे अयातुल्लाह सरकार को परापरकर एक नई सरकार बनायें और अधिनियम की बुनियाद रखें। उड़ेखनीय है कि ईरान में एक तब्का है, जो अयातुल्लाह सरकार से संतुष्ट नहीं है और ईरान का आधिनियमिकण चाहता है। हालांकि, ऐसा कोई सुवृत्त भी नहीं है कि ईरान किसी क्रांति के लिए तैयार है।

चीन की, तो वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगा है। अब देशों, विशेषकर खाड़ी के मुखों की तरफ से भी कोई आक्रामक बचान नहीं आया है और भारत भी शांति ही चाहता है और चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री नोंदे मोदी ने नेतन्याहु से बात करके यही संदेश दिया था कि बातचारी की मौत पर समस्याओं का हल निकलना चाहिए। यानी, अब फैसला नेतन्याहु को लेना है। हमें यह भी देखना होगा कि उन पर धरेलू राजनीति का बदला तज़ित की जाएगा। वैसे, ईरान के पास भी एक राते हैं स्थिति को भड़काने के बाद इजरायल पर ही निशाना नहीं लगाए। हो सकता है कि पश्चिम के देशों को दबाव में लाने के तैयार हैं।

## वक्फ प्रबंधन का काम राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया जाए

भारत में तीर्थ प्रबंधन का कानूनी नियमन बिट्ठि हुक्मत के दौरान धर्मार्थ और धार्मिक द्रस्त अधिनियम 1920 के साथ शुरू हुआ था, जो सभी समुदायों पर लागू हुआ था। तीन साल बाद इस क्षेत्र में पहला समुदाय विशेष कानून आया-मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती को केंद्रीय व प्रतिवादित विधायिकाओं के समर्थन मिलाए।

(ताहिर महमद, पूर्व अध्यक्ष, रा. अल्पसंचयक आयोग) केंद्र सरकार और मुसलम समुदाय के बीच कलह की ताजा वजह इस साल अगस्त में संसद में पेश दो वक्फ (संसोधन) विधेयक हैं। उनके धोषित और कथित मकसद की सत्यता का अकलन देश में वक्फ प्रबंधन के इतिहास को ध्वनि में रखने हुए है। वक्फ, एक अर्थी ईरानी के बावजूद देश अपनी धर्मार्थ की गई संपत्ति को दर्शाता है। यह उपरान्त, दान वा वसीयत से हासिल होता है। इस साल में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी वक्फ हैं।

भारत में तीर्थ प्रबंधन का कानूनी नियमन बिट्ठि हुक्मत के अधीन धर्मार्थ और धार्मिक द्रस्त अधिनियम 1920 के साथ शुरू हुआ था, जो सभी समुदायों पर लागू हुआ था। तीन साल बाद इस क्षेत्र में पहला समुदाय विशेष कानून आया-मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती को केंद्रीय व प्रतिवादित विधायिकाओं के समर्थन मिलाए।

मुसलिम समुदाय के लिए संसद ने 1954 में एक सामान्य वक्फ अधिनियम बनाया था और 1955 में देश के सबसे बड़े वक्फ अधिनियम में विशेष कानून भी लागू हुआ। ऑडिशा में जगत्राय मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ, तिरुपति में श्री वैक्षेष्ठर मंदिर और जम्मू-कश्मीर में प्रमुख वक्फोंकी विशेष कानून लागू हुए।



साल 2014 और 2019 में भी बदलाव हुए। कुल मिलाकर, वक्फ प्रबंधन से जुड़े भारतीय कानून दर्शनीय हालत में हैं। इसके चलते भी स्थानांतरिक विशेष कानूनों में विशेषादेवी जैसे प्रमुख वक्फोंकी विशेष कानून लागू हुए।

बहरहाल, आज यह दावा करता है कि किसी समुदाय के धार्मिक स्थलों के बारे में भी कोई आधिकार नहीं है, हक्कीकत से अब भ

## महाराष्ट्र में नया बवाल- सीएम दल-बल आए, खाए-पीए और चले गए, अब तक ना चुकाया 1.58 करोड़ का बिल

सड़कों के लिए केंद्र से मिली मदद  
पर हिमाचल सरकार में मंत्री  
विक्रमादित्य सिंह ने खुशी जाहिर की



शिमला, एजरी। हिमाचल प्रदेश सङ्कों के लिए केंद्र से मिली मदद पर हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हम हिमाचल प्रदेश के हित में कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार से, केंद्रीय सङ्क अवसंरचना निधि के रूप में, हिमाचल प्रदेश को सहायता मिली है। हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें कई सङ्कों और ब्रिज शामिल हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखिंद्र सिंह सुखबू के स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए थे। इस दौरान महाराष्ट्र का एक शिष्टमंडल भी उनके साथ गया था, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए उस बैठक में शामिल हुआ था। दावोंस प्रवास के दौरान एक कंपनी ने इन लोगों का आतिथ्य स्वतंकार किया। शिष्टमंडल होटल में जहां ठहरा और खाया-पीया, उसका कथित तौर पर भुगतान नहीं किया गया। इसलिए उस कंपनी ने 1.58 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने में विफल रहने पर महाराष्ट्र सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है।

2 हफ्ते में दूसरी बार कल्याण बोर्ड दांव,

विभाग ने निरंतर इन परियोजनाओं की वकालत की और राज्य की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से प्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों में शिमला में 52 किलोमीटर टिक्कर-जरोल-गहन-ननखड़ी-खमाड़ी सड़क के उन्नयन के लिये 54.87 करोड़ रुपये, हमीरपुर में 20 किलोमीटर सुजानपुर टीहारा-सधोल सड़क के लिये 41.10 करोड़ रुपये, हमीरपुर में 37 किलोमीटर नवगांव-बेरी सड़क के लिये 79.25 करोड़ रुपये, कांगड़ा में गज खड़ पर 828 मीटर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिये 86.34 करोड़ रुपये तथा मंडी में 9.6 किलोमीटर बखरोट-करसोग-सनारती-सैंज सड़क के उन्नयन के लिये 31.80 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है।

जैन समुदाय पर क्यों शिद्द सरकार महरबान

हिमाचल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल का अनुपाय बनेगा।

**का अनुसरण करगा : मत्रा**  
 शिमला, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल का अध्ययन कर लौटे ठाकुर ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा की और सर्वोत्तम उपायों को साझा करने पर सहमति जताई। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यहां शुक्रवार को बताया कि पहाड़ी राज्य उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल का अनुसरण करेगा और दोनों प्रदेश शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सर्वोत्तम उपायों का अनुसरण करेगा। इसके लिए उन्हें अब से एक टेस्ट पास करना होगा। तब से तीनों सेनाओं अनिवारीयों की लगातार भर्ती हो रही है।

को साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल का अध्ययन कर लौटे ठाकुर ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा की और सर्वोत्तम उपायों को साझा करने पर सहमति जारी। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई सकारात्मक पहल के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक रूपरेखा तैयार की जाएगी।

जरए एक्सप्रेस वे कौ सेंट्रल वर्ज तक सिर्फ टैंकर और पानी सप्लाई के पाइप की सिंचाइ में पानी का रिसाव कम होता है। पदाधिकारया का नियुक्त का जा रहा है। दूसर दला स ऐसे में इस निर्वाचन क्षेत्र का विकास थम गया है।

## ଫ୍ରେ ଫ୍ରୀ ନଡ଼ି

लैंसडाउन एसडाइएम शालिना भाय, पुनर्स व एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई. धायलों को निकालने में स्थानीय युवाओं ने भी सहयोग किया। हादसे में तीन बारातियों मुकेश सिंह (35) निवासी गुनियाल, दूल्हे की मौसीरी बहन नूतन (35), धीरज सिंह (65) निवासी गुनियाल की मौत हो गई, जबकि 10 लोग धायल हो गए। वाहन में सवार दो बच्चे सुरक्षित हैं। धायलों को उपचार के लिए वेस अस्पताल कोटद्वारा में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत अस्पताल पहुंचे और उन्होंने डॉक्टरों को धायलों को उचित उपचार के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अस्पताल में लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला। लोग सडक की खस्ताहालत को लेकर

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह

सुखखू अलग-अलग माँकों पर अलग-अलग बात करते हैं। उन्होंने कहा, जब वह हिमाचल प्रदेश में और चुनावों के दौरान बोलते हैं तो कहते हैं कि राजनीतिकों को केंद्र से कुछ नहीं मिलता, जबविधायक दूसरी तरफ, दिल्ली में वह वित्तीय मदद के लिए आभार व्यक्त करते हैं और अधिक मदद की गुहार लगाते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में केंद्र की मदद के बिना एक दिन भी सरकार नहीं चला सकती, लेकिन राज्य सरकार के पास इस बात का कोई हिसाब नहीं है कि पैसा कहां खर्च होता है।

कर्मचारियों का वेतन न देकर सुख्खा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने इसे मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी आपदा बताया। मंत्री ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में नशाखोरी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 5,600 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्ती मामले में कांग्रेस के नेता की सलिमता पार्द गई। जहां पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं, या बंद हो गए हैं। केंद्र सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छह करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है, जो हर वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये की बनियादी लांच

भाजपा नेता ने कहा, कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस (का मतलब) अपराधीकरण और कमीशन है। नव्हा ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य को पीछे को ओर ले जा रही है लाख कराड़ संपत्ति का बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, तेज गति से वाहन चलाने के लिए अनुकूल आठ राष्ट्रीय गलियारों और आठ रूट पर रेल लाइन बिछाने को मंजूरी दी है।

जर्मनी-कृतियों में सरकार गठन से पहले 5 विधायिकाओं को मनोनीत करने पर हंगामा, विरोध में उतरी कांग्रेस



जम्मू-कश्मीर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन से पहले 5 विधायकों के मनोनीत करने के कदम पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। उसने ऐसे किसी भी फैसले को लोकतंत्र और सविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करार दिया। खबरों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में पहली बार नई सरकार के गठन में पांच मनोनीत विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्र शासित प्रदेश में एक दशक के अंतराल के बाद चुनाव हुए हैं। गृह मंत्रालय की सलाह के आधार पर उपराज्यपाल इन सदस्यों को नामित करेंगे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पिछले साल 26 जुलाई 2023 को संसोधन करने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई। 5 विधायकों को मनोनीत किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सदस्य संख्या 95 हो जाएगी, जिससे सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमटी के वरिष्ठ उपायक्षम और मुख्य प्रवक्ता रवींद्र शर्मा ने कहा, 'हम जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन से पहले उपराज्यपाल की ओर से पांच विधायकों को मनोनीत करने का विरोध करते हैं। ऐसा कोई भी कदम लोकतंत्र, जनादेश और सविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करने के समान है।' कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर अपनी असहमति और विरोध जताया। साथ ही, इसका डटकर मुकाबला करने की घोषणा की। इस दौरान पार्टी नेता रमन भल्ला भी मौजूद थे। शर्मा ने कहा, 'सविधान के मुताबिक, उपराज्यपाल को मत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। चुनाव के बाद बहुमत या अल्पमत की स्थिति को बदलने के लिए मनोनीयन के प्रावधान का दुरुपयोग करना हानिकारक होगा।' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार उपराज्यपाल के पास कश्मीरी पांडियों और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के शरणार्थियों सहित 5 विधायकों को नामित करने का अधिकार है।

जम्मू-कश्मीर में सरकार की शवितयों में  
कटौती के प्रयास की बात को गृह  
मंत्रालय ने किया खारिज

## पीएम मोदी का मंदिर बनवाने वाले कार्यकर्ता ने भाजपा छोड़ी

A photograph of a man in a blue shirt, standing in front of a wall featuring a portrait of Narendra Modi. The man is gesturing with his hands while speaking. The background includes a small Indian flag and some text.

आने वालों को पार्टी के विभिन्न पद दिए जा रहे हैं। मुंडे ने कहा कि पुराने पदाधिकारियों का अपमान हो रहा है। अब उन्हें पार्टी की बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता है। उनकी राय तक नहीं सुनी जा रही और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर कर दिया गया है। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मुंडे ने कहा, मौजूदा विधायक उन लोगों के इलाकों में विकास निधि खर्च कर रहे हैं जो दूसरी पार्टीयों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक को बीते 5 साल में शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी 2 प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन मिला। उन्होंने इसके लिए एकोई प्रयास भी नहीं किया। ऐसे में इस निवारण न क्षेत्र का विकास थम गया है।





